मि.यू.में ऊर्जा की मांग

(कुल ऊर्जा खपत में %)

श्रेणी	1997-98	1998-99 अनुमानित	1999-2000	2000-01	2001-02
कृषि	89418	94369	99325	104238	108249
	(26.13)	(25.61)	(25.14)	(24.70)	(24.10)
उद्योग	136917	147123	156575	165837	175093
	(40.01)	(39.93)	(39.64)	(39.30)	(39.00)
वाणिज्यिक	23829	25577	27442	29433	31559
	(6.96)	(6.94)	(6.95)	(6.98)	(7.03)
विविध घरेलू	70555	78210	86559	95662	105586
	(20.61)	(21.22)	(21.91)	(22.67)	(23.52)
कुल (अन्य को मिलाकर)	342253	368507	395042	421953	448996
	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)

(ग) नौंवीं योजनाके प्रारूप में योजना आयोग ने 40245 मे.वा.क्षमता अभिवृद्वि कार्यक्रम की परिकल्पना की हैं । उपरोक्त के अतिरिक्त बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

(i) विद्यमान सुविधाओं से विद्युत उत्पादन अधिकतम करना ।

(ii) निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विद्युत क्षेत्र में प्रक्रियाओं को सरल बनाना और सुधार कार्य आरम्भ करना ।

(iii) मांग पक्ष प्रबन्धन और ऊर्जा सरंक्षण ।

(iv) अन्तर्राज्यीय/अन्तक्षेत्रीय आदान प्रदान को प्रोत्साहन ।

(v) पारेषण और वितरण हानियों में कमी ।

बिहार में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में धोखाधड़ी

900. **श्री एस.एस.कृष्णा**: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान 2 फरवरी,1999 के द हिन्दुस्तान टाइम्स में "मैसिव रैकेट डिटेक्टेड इन बिहारस पावर्टी एलीविएसन प्रोग्राम्स" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है,यदि हां,तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया हैं;

(ख) उनके मंत्रालय में ऐसे कार्यक्रमों पर किस प्रकार निगरानी रखी जाती है और ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत निधियों के वितरण के संबंध में राज्य की मशीनरी और उत्तरदायी बैंकों को किस प्रकार शामिल किया जाता है;और

(ग) क्या हाल में उनके मंत्रालय ने कर्नाटक के ग्रामीण विकास की योजनाओं की समीक्षा की है,यदि हां,तो अब तक किये गये सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबा गौडा पाटील): (क) ऐसा कोई समाचार दिनांक 2 फरवरी,1999 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में नहीं छपा । तथापि प्रश्न में बताया गया समाचार 12.2.1999 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपा हैं । राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे इस मामले की पूर्ण,निष्पक्ष और विस्तृत जांच करें तथा संघ सरकार को रिपोर्ट भेजें ।

(ख) सावधिक प्रगति रिपोर्टो/विवरणियों,राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा गहन क्षेत्रीय निरीक्षणों,

मंत्रालय की क्षेत्रीय अधिकारी योजना;ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु राज्य स्तरीय समन्वय समिति जैसी विभिन्न समितियों द्वारा समीक्षा;जिला ग्रामीण विकास एजेसियों के परियोजना निदेशकों तथा ग्रामीण विकास के राज्य सचिवों के सम्मेलनों;समवर्ती मूल्यांकनों और वीडियों कांफ्रेंस के माध्यम से मंत्रालय के समस्त कार्यक्रमों की निगरानी की जाती हैं । इसके अतिरिक्त,राज्य जिला/ब्लाक स्तरों पर सतर्कता एंव निगरानी समितियां गठित करने की भी निर्देश जारी किए गए हैं । ब्लाक स्तरीय बैंकर्स समिति,जिला स्तरीय समन्वय समिति तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के माध्यम से समय-समय पर बैंकों द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी की जाती हैं ।

(ग) जी,हां । कर्नाटक में दस लाख कुओं की योजना तथा इन्दिरा आवास योजना का मूल्यांकन किया जा रहा हैं ।

Asistance for Poverty Alleviation Programme in Bihar

901. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the annual Central assistance for poverty alleviation programme in Bihar;

(b) whether Government have made any exercise to know that extent of utilisation of the allocated funds for implementation of the programme and achievements, particularly in respect of housing schemes for people below the poverty line under the Indira Awas Yojna;

(c) if so, the details thereof stating whether any case of misappropriation of funds has been detected; and

(d) the steps taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) An amount of Rs. 898.88 crore has been allocated by the Centre to Bihar in 1998-99 under poverty alleviation programmes, excluding Employment Assurance Scheme (EAS). While funds are not allocated to States under EAS, an amount of Rs. 158.26 crore has been released to Bihar during April to December, 1998.

(b) to (d) Yes, Sir. As per the latest report available the State has utilized 55.55% available funds till December, 1998. The percentage utilisation of total allocation of funds and physical achievement under different poverty alleviation programmes including Indira Awaas Yojana upto December, 1998 is as under:—

SI No.	Programme	%Utilisation to total allocated funds	Unit	Physical Achieve - ment
1.	Jawahar Rozgar Yojana (JRY)	59.68	Lakh Mandays	412.04
2.	Indira Awaas Yojana (IAY)	50.16	Houses (Nos.)	76419
3.	Million Wells Scheme (MWS)	33.72	Wells (Nos.)	9680
4.	Employment Assurance Scheme (EAS)	*	Lakh Mandays	270.96
5.	Development of Women and Children in Rural Areas (DWCRA)	11.41	Group (Nos.)	2123